तैयारी

खिलौनों के निर्माण में चीन को चुनौती देने की रणनीति, केंद्र सरकार ने की अलग से फंड की व्यवस्था

चित्रकूट, नोएडा व वाराणसी में बनेंगे खिलौना क्लस्टर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। खिलौने के निर्माण में चीन को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से फंड की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यूपी में भी खिलौना क्लस्टर हब विकसित किए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ चित्रकूट और वाराणसी इसके प्रमुख गढ़ होंगे। इनके अलावा कम से कम 15 और जिलों में खिलौना क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसमें गोरखपुर-झांसी सहित कई अन्य जिले शामिल होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में चीन का एकछत्र राज्य है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में बिकने वाले करीब 75 फीसदी खिलौने चीन में बन रहे हैं। इस बाजार में अब भारत भी सेंध लगाएगा।

खिलौना निर्माण के लिए प्रस्तावित नेशनल एक्शन प्लान में क्लस्टरों का विकास, कौशल निर्माण और निर्माण ईको सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके जरिये उच्च गुणवत्तायुक्त, इनोवेटिव और ईको फ्रेंडली खिलौने बनाए जाएंगे।

खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के सेक्टर 33 में 100 एकड़ पर टॉय पार्क बन रहा है। इसमें खिलौना निर्माण फैक्टरी के लिए करीब 150 उद्यमियों को भूखंड दिया जा चुका है। इससे करीब 500 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के तहत पार्क को बनाया जा रहा है।

खिलौनों की गुणवत्ता बड़ी चुनौती

दुनियाभर में जहां खिलौने की मांग में हर साल पांच फीसदी की वृद्धि हो रही है, वहीं भारत में यह वृद्धि दर 15 फीसदी तक है। भारत से अभी करीब 20 अरब रुपये के खिलौने का निर्यात हो रहा है, लेकिन ज्यादातर खिलौना निर्माता असंगठित हैं और खिलौने की गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती है। निर्माण में लागत ज्यादा होने से भारतीय खिलौने घरेलू बाजार में ही आयातित खिलौने से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। बजट में आवंटित राशि से इन्ही चुनौतियों से निपटा जाएगा।

प्रोत्साहन के लिए बनेगी विशेष योजना

गोरखपुर के टेराकोटा और झांसी के मल्टीकलर डॉल्स, बर्ड जैसे खिलौनों की मांग भी बाजार में तेजी से बढ़ी है। वाराणसी और चित्रकूट के खिलौने भी बाजार में पसंद किए जा रहे हैं। इन जिलों में खिलौना क्लस्टर का विकास एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत किया जाएगा।खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। पूरे सेक्टर को कवर करने के लिए एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। इसका नोडल विभाग एमएसएमई होगा। इससे वर्ष 2025 के अंत तक देश का खिलौना उद्योग 200 अरब रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है।